

तैयारी

सरकार निवेशकों को देगी बड़ी रियायत, एक्सप्रेस के किनारे लीज पर जमीन देने की तैयारी

सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगी सस्ती जमीन

लखनऊ, विशेष संचाददाता। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे किनारे सोलर पार्क विकसित करने का काम सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होगा। इसके लिए सरकार निवेशकों को सस्ती दर पर जमीन लीज पर उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। यहां 50-50 मेगावाट के हिसाब से सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसे इसी महीने कैबिनेट की बैठक से पास कराया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक निवेशकों की मांग को देखते हुए सरकार ने यहां जमीन सस्ती देने का निर्णय लिया है। यहां लीज रेंट 15 हजार रुपये प्रति एकड़



है। अब इसे निवेशकों से न लेने का प्रस्ताव रखा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध भूमि पर 450 मेगावाट सौर ऊर्जा के सोलर प्लांट लग सकते हैं। इसमें लगभग 2550 करोड़ रुपये का निवेश होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सोलर इनर्जी संयंत्र लगाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने रुचि

- इंडस्ट्री विभाग के इस प्रस्ताव को इसी माह कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी
- दर्जन भर से ज्यादा कंपनियां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर प्लांट लगाने को तैयार

दिखाई है। लेकिन सरकार इनसे सस्ते में सौर ऊर्जा खरीदेगी। इससे सरकार जमीन की रियायत में होने वाली नुकसान की भरपाई कर लेगी। यहां एक पैकेज कम से कम 50 मेगावाट का होगा। दोनों ओर इस तरह के 18 पैकेज होंगे। हर पैकेज 50 किमी की दूरी पर होगा। हाल में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने लीज

ये कंपनियां आगे आईं

टाटा पॉवर, जीएमआर एनर्जी, महाप्रीत, एनटीपीसी, आत्रिया पॉवर, सात्विक ग्रीन, ओएमसी पॉवर, टोररेंट पॉवर, अडानी सोलर एनर्जी, आरएवीसी सॉल्यूशन, अवाडा ग्रुप, एचपीएम सोलर, नोवासा ग्रीन।

रेंट न लेने का निर्णय करते हुए कहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जल्द ही उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निवेशकों को सोलर पार्क में सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। उनका कहना है कि पेट्रोलिंग वाहन व सुरक्षा कर्मी इसकी निगरानी करेंगे।